बिहार के विकास में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विधायकों की भूमिका : (2010–2020 के विशेष संदर्भ में)

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वरनगर, दरभंगा

के

सामाजिक विज्ञान संकाय

(राजनीति विज्ञान)

में

पी–एच0 डी0 उपाधि हेतु

प्रस्तावित शोध–प्रारूप की रूपरेखा

शोध पर्यवेक्षक	शोधार्थी
डॉ0 राजीव रौशन	धर्मेन्द्र कुमार पासवान
सहायक प्राध्यापक	राजनीति विज्ञान
राजनीति विज्ञान विभाग	PAT क्रमांक–E2216005
आर. एन. ए. आर. कॉलेज,	वर्ग क्रमांक–06
समस्तीपुर	PAT : 2021–2022

Dr. Rajeev Roushan
Assistant Professor
Department of Political Science

R. N. A. R. College, Samastipur
L.N. Mithila University, Darbhanga
Mob.-7909088589
Email : polscrnarc@gmail.com

Date 18-04-2024

Ref. No............

CONSENT LETTER

I, Dr Rajeev Roushan, Assistant Professor, Department of Political Science, R.N.A.R. College, Samastipur, L.N.M.U., Darbhanga, henceforth give my consent to be the Ph.D. Research Supervisor of Mr. Dharmendra Kumar Paswan , UGC- NET (JRF), Research Scholar, enrolled under PAT -2021-2022, Roll No. E2216005, Class Roll No. 06, during his entire Ph.D. Research Work . The title of his Ph.D. Research is "बिहार के विकास में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विधायकों की भूमिका: (2010–2020 के विशेष संदर्भ में)"

I wish him all success in his endavour.

R. Roushan
18.04.24
(Dr. Rajeev Roushan)
Supervisor

Dr. Rajeev Roushan
Assistant Professor & Head
Dept. of Political Science
R.N.A.R. College, Samastipur

LALIT NARAYAN MITHILA UNIVERSITY

KAMESHWARANAGAR, DARBHANGA – 846004
(EXAMINATION DEPARTMENT)

Information regarding Ph.D Supervisor

1. Name & Address of Supervisor : DR. RAJEEV ROUSHAN
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
R.N.A.R. COLLEGE, SAMASTIPUR
2. Position : ASSISTANT PROFESSOR
3. Nature of appointment : Temporary/Permanent
4. Area & Specialisation : INTERNATIONAL RELATION & LOCAL ADMINISTRATION
5. How many Students are doing research under your supervision : 02
6. Provide following details :

Sl. No.	Name of Student	PRT Roll No./ Univ. Reg. No.	Date of Ph.D Registration	Date of Submission of Synopsis	Full Research Topic
1.	RAVINDRA KUMAR RAVI	990206	23.03.21		"दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में भारत की भूमिका : एक अध्ययन"
2.	SURAJ KUMAR DAS	E990354	18.03.21		बिहार में न्याय के साथ विकास की अवधारणा : एक अध्ययन (2005-2020)
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

Attach extra sheet if required.

R. Roushan 18.04.24
Signature of Supervisor
(with Name & Date)
Dr. Rajeev Roushan
Assistant Professor & Head
Dept. of Political Science
R.N.A.R. College, Samastipur

20.04.24
Signature of H.O.D.
(With Name & Date)
Head
University Department of Political Science
Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga

Dean
(With Name & Date)

Lalit Narayan Mithila University

Kameshwarnagar, Darbhanga
(Examination Department)

University Department Of Political Science

Ref.no....131/24 Date...18/4/24

Course Work Completion Certificate For Ph.D. Programme - PAT-2021

(AS PER THE PH.D. REGULATIONS APPROVED BY THE CHANCELLOR VIDE MEMO NO.: BSU-05/2010-2684/GS(I) DATED 20.9.2017)

This is to certify that Mr/Ms..

Dharmendra Kumar Paswan

on being enrolled as Ph.D. Course Work student with Enrolment No.. E2216005 on 17-05-2023 ....in the **University Department of Political Science** under the Ph.D. regulations of the University framed as per the UGC Guidelines, 2016 has successfully completed his/her course Work of One Semester (Six months) on 25-11-2023.

HOD
Department of Political Science
L.N.M.U, Darbhanga

Head
University Department of Political Science
Lalit Naray Mithila University, Darbhanga

11
15-4-24

Undertaking by the

I...DHARMENDRA KUMAR PASWAN..........son/daughter of...FANI BHUSHAN PASWAN...resident of village....RAMPUR.......... Post Office...AMARPUR... Police Station...AMARPUR....... District ..BHAGALPUR.......... and having PAT 2021, Roll No. E ..2216005.......... Class Roll.No ....96...... am enrolled in Ph.D Coursework in the University department of Political Science, L.N. Mithila University, Darbhanga from 25.05.2023 to 25.11.2023.During this period I remained present in the class. Further, I declare that I did not undertake any remunerative work nor took any remuneration/honorarium from any other sources during above mentioned period.

I hereby, declare that the above mentioned declaration is true to the best of my knowledge and if found incorrect at any level, I shall be solely responsible.

NOTARY
KIRAN KUMARI
Exp.-July 2027
DARBHANGA
GOVT. OF BIHAR

Dharmendra Kumar

I identify that the signature of the Deponent who has signed in my presence

Sri/Smt. Dharmendra Kr Paswan
Who is Identified by Sri/Smt. A N Shrivastava 15/04/2024
Advocate Solemnly Affirmed and Declared before me.

15-4-24

KIRAN KUMARI
Notary, Darbhanga

शोध कार्य का शीर्षक (Title of Research)-:

बिहार के विकास में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विधायकों की भूमिका: (2005-2020 ई. के विशेष संदर्भ में)

❖ शोध समस्या का प्राक्कथन (Statement of the Research Problem)-:

बिहार अपने प्राचीन काल से ही सभ्यता, ज्ञान और शक्ति का केंद्र बिंदु रहा है। जिसने समृद्ध राजनीति के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपरा से पूरे विश्व को आलोकित्त किया है। विश्व में प्रथम गणतंत्र की जन्मस्थली बिहार ही रही है। संविधान लागू होने के पश्चात प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. श्री कृष्ण सिंह के समय में विभिन्न क्षेत्रों में परियोजना की शुरुआत की गई तथा कृषि एवं उद्योग के क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया गया। श्री सिंह के बाद बने मुख्यमंत्रियों ने इन विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया। लेकिन सामाजिक न्याय की अवधारणा या आदर्श को आगे बढ़ाने में कर्पूरी ठाकुर जी का बहुमूल्य योगदान है। इनके पश्चात के मुख्यमंत्रीयो ने भी बिहार विकास के दम भरे लेकिन बिहार हर एक क्षेत्र में पिछड़ता चला गया। चाहे वह कृषि,उद्योग, प्रशासनिक व्यवस्था,कानून व्यवस्था, रोजगार आदि ही क्यों ना हो। इन क्षेत्रों में बिहार की देश के विभिन्न राज्यों में सबसे निचले पायदान पर गिनती होने लगी। जब 2005 में बिहार में श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता में आरूढ़ हुए। तब से अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण दिखने लगा। साथ ही इनके शासनकाल में विकास के बड़े परिवर्तन देखने को मिला। जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क और परिवहन का भी विकास हुआ। इन्होंने महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए विशेष कार्यक्रमों की शुरुआत की। बिहार विधानमंडल के विधान सभा में कुल 243 सीटे है। जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट आरक्षित है।

बिहार विधानमंडल के दोनो सदनों मे कार्य करने वाले अनूसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विधायको ने बिहार के विकास के लिए कार्य किए फिर भी कुछ प्रश्न उभर कर सामने आते है जो इस प्रकार है –

➢ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विधायकों को अपनी उत्तरदायित्व को पूर्ण करने में किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा ?

1

Dharmendra kumar
16-04-2024

R. Roushan
18.04.24

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विधायकों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही ?

- बिहार के विकास में बिहार विधान मंडल के दोनो सदनों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विधायक अपनी भूमिका का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने में क्या सफल रहे ?

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूची जनजाति को इनके प्रतिनिधि विधायकगण सामाजिक न्याय दिलाने में क्या सफल रहे ?

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विधायकों का राजनीतिक चेतना के विकास में क्या योगदान रहा ?

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष विधायक एवं महिला विधायकों की कार्य पद्धति में क्या रहा ?

❖ शोध का आच्छादन: सारतत्व एवं क्षेत्र (Research coverage:Theme and Area):-

प्राचीन काल में कभी मगध,अंग,विदेह, वज्जीसंघ, अंगुत्तराव कौशकी एवं समुद्दोत्तर के रूप मे चिन्हित भौगोलिक क्षेत्र को ही आज बिहार के रूप में जाना जाता है। बिहार अनेक समय महत्वपूर्ण साम्राज्यों का केंद्र रहा है। जिसमें मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और पाल साम्राज्य शामिल है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ज्ञान की भूमि रही है।बिहार वह जगह है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान और निर्वाण प्राप्त हुआ। बोधगया और वैशाली जैसे कहीं ऐतिहासिक धरोहर है। बिहार की सांस्कृतिक रुप से भी समृद्ध रही है। यहां की प्रमुख कला मधुबनी पेंटिंग, लोक नृत्य व लोकगीत बहुत ही प्रसिद्ध रही है।

12 दिसंबर 1911 को जब ब्रिटिश सम्राट जार्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में बिहार एवं उडीसा को मिलाकर बंगाल से पृथक एक प्रांत की घोषणा की तब 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा दोनों अलग एक प्रांत के रूप में बंगाल से अलग हो गए। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उडीसा अलग प्रांत बन गए। बिहार का मुख्यालय पटना निर्धारित किया गया। भारतीय संविधान लागू होने के पश्चात बिहार विधानसभा

Dharmendra Kumar 18-04-2024 R. Roushan 18.04.24

में निर्वाचित कुल 324 सदस्य थे। जिसमें सामान्य सीट 248 , अनुसूचित जातियों के लिए 48 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 28 सीट आरक्षित किया गया।

नवम्बर 2000 मे भारतीय संसद द्वारा बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित कर बिहार से अलग झारखंड राज्य बनाया गया। इसके फलस्वरुप बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचित कुल 324 सदस्यों में से 82 सदस्य झारखंड विधानसभा के सदस्य हो गये। बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य शेष रह गए हैं। परिसीमन अधिनियम, 2002 के अनुसार बिहार विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 243 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 38 है। जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित है। ठीक उसी तरह 1937 में बिहार विधान परिषद में सदस्यो की संख्या 30 थी। संविधान लागू होने के बाद 72 कर दी गई, वर्ष 1958 में यह संख्या बढ़कर 96 हो गई जो वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद की संख्या घटकर 75 हो गई। जो वर्तमान में इसी स्वरूप मे है।

स्वतंत्रता से पूर्व बिहार एक औद्योगिक राज्य के रूप में विकसित था। खनिज संसाधन की उपलब्धता, यातायात की सुविधा थी। गंगा नदी सीधे बंगाल की खाड़ी से मिल जाती थी। वहां से व्यापार वाणिज्य हुआ करता था। स्वतंत्रता से पूर्व अनेक महत्वपूर्ण उद्योग थे जिसमें इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग और चीनी उद्योग आदि शामिल थे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2007 से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समग्र विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती कल्याण विभाग का पुनर्गठन कर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के रूप में स्वतंत्र विभाग का गठन किया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के बहुमुखी विकास हेतु निरंतर कई योजनाओं को चलाया जा रहे हैं जैसे -1.मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना 2. मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 3.प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र 4. मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना 5. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना इत्यादि जो इनके 2005 ,2010 और 2020 के शासनकाल में परिलक्षित होती है।

शोध के विषय के आधार पर कानून बनाने वाली संस्था यानी विधायिका बिहार विधानमंडल के कार्य शक्तियां तथा विशेषाधिकारों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। शोध क्षेत्र के अंतर्गत देश की आजादी के पहले बिहार में विधायक की स्थिति एवं कार्य प्रणाली तथा भारतीय संविधान लागू होने के पश्चात बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व एवं उसके कार्य प्रणाली का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाना है। साथ ही बिहार के विकास में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित

Dharmendra Kumar
18-04-2024

R. Roushan
18.04.24

जनजाति विधायको के योगदान को बताया जाएगा। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में प्रतिनिधित्व के पश्चात सामाजिक , आर्थिक , राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विकास में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों का योगदान को बताया जाएगा । एवं बिहार के वैसे मुख्यमंत्री जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्ग से रहे हैं । उनके कार्यकाल की कार्य प्रणाली का विस्तार से अध्ययन करना है ।

❖ साहित्य का पुनरावलोकन (Review of literature):-

- **डॉ ए. एम. झा एवं डॉ मिन्नी ठाकुर द्वारा लिखित पुस्तक "बिहार सुशासन की ओर" (2012)**, में चर्चा की गई है की प्राचीन काल में बिहार का इतिहास स्वर्णिम रहा है और धीरे-धीरे बिहार किस तरह पिछड़ता चला गया और वर्तमान में बिहार की स्थिति क्या है? इस संपादित पुस्तक का उद्देश्य आम लोगों में बिहार के प्रति प्रचलित धारणाओं का खंडन करना है । जो बिहार के सुशासन के समग्र बिंदुओं को ध्यान में रखकर संकलित किया गया है ।

- **डॉ.जगन्नाथ मिश्र ने अपनी पुस्तक "बिहार विकास और संघर्ष"(2012)** में उनके दीर्घकालीन सामाजिक,आर्थिक एवं राजनितिक अनुभवों पर आधारित कई सुचिंतित निबंध संकलित है। साथ ही प्रस्तुत पुस्तक मे 1989 तक कि अहम राष्ट्रीय विशेष रूप से आर्थिक नीतियों से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण किया गया है। इसमें लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है ।

- **पंकज कुमार झा के द्वारा लिखित पुस्तक "सुशासन के आईने में नया बिहार"(2012)** में इस बात पर चर्चा की गई है की बिहार का लोकतंत्र का तीर्थ कहा जाता है। बिहार के लोकतंत्र में जाति है, रंगदारी है,छल कपट है, और बूथ की लुट भी है । लोकतांत्रिक राजनीति के बाद भी बिहार में बेहद गरीबी है, बदहाली है, सार्वजनिक जीवन की न्यूनतम सुविधाओं का घोर अभाव है । यह पुस्तक बिहार में लोकतांत्रिक राजनीति के उसे चेहरे को भेंट करती है जो भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक राजनीति का सबसे पेंचीदा सवाल है । बिहार में सुशासन तभी कारगर एवं प्रभावी होगा, जब भूमि सुधार, समान शिक्षा, किसान आयोग की सिफारिश को लागू किया जाएगा हालाकी एक सुखद पहलू है कि आज बिहार में तथा बिहार से बाहर रहने वाले प्रत्येक बिहारी के मन में साहस और गर्व की अनुभूति है ।

Dharmendra Kumar
18-04-2024

4

R. Roushan
18.04.24

जनजाति विधायको के योगदान को बताया जाएगा। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में प्रतिनिधित्व के पश्चात सामाजिक , आर्थिक , राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विकास में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों का योगदान को बताया जाएगा । एवं बिहार के वैसे मुख्यमंत्री जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्ग से रहे हैं। उनके कार्यकाल की कार्य प्रणाली का विस्तार से अध्ययन करना है।

❖ साहित्य का पुनरावलोकन (Review of literature):-

- **डॉ ए. एम. झा एवं डॉ मिन्नी ठाकुर द्वारा लिखित पुस्तक "बिहार सुशासन की ओर" (2012)**, में चर्चा की गई है की प्राचीन काल में बिहार का इतिहास स्वर्णिम रहा है और धीरे-धीरे बिहार किस तरह पिछड़ता चला गया और वर्तमान में बिहार की स्थिति क्या है? इस संपादित पुस्तक का उद्देश्य आम लोगों में बिहार के प्रति प्रचलित धारणाओं का खंडन करना है। जो बिहार के सुशासन के समग्र बिंदुओं को ध्यान में रखकर संकलित किया गया है।

- **डॉ.जगन्नाथ मिश्र ने अपनी पुस्तक "बिहार विकास और संघर्ष"(2012)** में उनके दीर्घकालीन सामाजिक,आर्थिक एवं राजनितिक अनुभवों पर आधारित कई सुचिंतित निबंध संकलित है। साथ ही प्रस्तुत पुस्तक मे 1989 तक कि अहम राष्ट्रीय विशेष रूप से आर्थिक नीतियों से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण किया गया है। इसमें लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है।

- **पंकज कुमार झा के द्वारा लिखित पुस्तक "सुशासन के आईने में नया बिहार"(2012)** में इस बात पर चर्चा की गई है की बिहार का लोकतंत्र का तीर्थ कहा जाता है। बिहार के लोकतंत्र में जाति है, रंगदारी है,छल कपट है, और बूथ की लुट भी है। लोकतांत्रिक राजनीति के बाद भी बिहार में बेहद गरीबी है, बदहाली है, सार्वजनिक जीवन की न्यूनतम सुविधाओं का घोर अभाव है। यह पुस्तक बिहार में लोकतांत्रिक राजनीति के उसे चेहरे को भेंट करती है जो भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक राजनीति का सबसे पेंचीदा सवाल है। बिहार में सुशासन तभी कारगर एवं प्रभावी होगा, जब भूमि सुधार, समान शिक्षा, किसान आयोग की सिफारिश को लागू किया जाएगा हालाकी एक सुखद पहलू है कि आज बिहार में तथा बिहार से बाहर रहने वाले प्रत्येक बिहारी के मन में साहस और गर्व की अनुभूति है।

Dharmendra Kumar
18-04-2024

R. Roushan
18.04.24

➢ **अशोक कुमार सिंह द्वारा लिखित पुस्तक "बिहार के 25 महानायक"(2021)**,में इस बात पर चर्चा कि गई है कि इसमें राजनीतिक, कला, साहित्य, संस्कृति, शिल्प, सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा के साथ अपने प्रयास से बिहार को एक स्वतंत्र पहचान दिलाने वाले नायकों का जीवंत वर्णन है। पुस्तक में व्यक्तित्व एवं कृतित्व के अनछुए पहलुओं को ज्ञानवर्धक तरीके से प्रस्तुत किया गया है।

➢ **रजनी कोठारी द्वारा लिखित पुस्तक 'कॉस्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स'(2010)**, वर्णन किया गया है कि "भारतीय राजनीति जातिवादी है तथा जाति राजनीतिकृत है"! पारंपरिक और आधुनिक राजनीति के बीच प्रचलित विभाजन को स्वीकार करते हुए '**कॉस्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स**' एक दिए गए समुदाय और क्षेत्रीय व्यवस्था में उनकी अंतः क्रिया की जांच करती है।

➢ **रजनी कोठारी द्वारा लिखित पुस्तक लोक थिंतक ग्रंथ माला 'राजनीति की किताब'(2018)**. में इस बात पर चर्चा की गई है कि लोकतांत्रिक राजनीतिक मुल्य आवश्यकताओ की राजनीति से होती है। जिसके कारण पारंपरिक समाज और उसके नेतृत्व का जुड़ाव होता है। वर्तमान लोकतान्त्रिक राजनीति में जाति प्रथा विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की राजनीतिक गोलबंदी के लिए संरचनात्मक एवं विचारात्मक स्थिति पर विस्तार से चर्चा किया गया है।

➢ **डॉ महेश्वर दत्त द्वारा लिखित पुस्तक 'गांधी अंबेडकर और दलित'(2022)**. गांधी और अंबेडकर दोनों की दृष्टि से दलित मुक्ति की चर्चा का प्रयास करती हैं। इस पुस्तक में मूलतः गांधी, अंबेडकर के दृष्टिकोण से वर्ण जाति, हिंदू धर्म शास्त्र और अस्पृश्यता की उत्पत्ति, प्रकृति , दलितों का उत्पीड़न तथा उत्थान की राजनीति से जुड़े हुए विषयों का तुलनात्मक वर्णन एवं विश्लेषनात्मक अध्ययन करती है।

➢ **राजकिशोर द्वारा लिखित पुस्तक 'दलित राजनीति की समस्या'(2008)**.यह पुस्तक दलित राजनीति से जुड़े तमाम प्रश्नों दलित राजनीति के लिए एक नई चुनौती पेश करती है। दलित राजनीति के जनक डॉ. अंबेडकर को विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा हथियाए जाने की चर्चा करती हैं।

➢ **चौधरी प्रसन्न कुमार और श्रीकांत द्वारा लिखित पुस्तक 'स्वर्ग पर धावा- बिहार में दलित आंदोलन (1912 – 2000)'.(2015)** प्रस्तुत पुस्तक में इस बात पर चर्चा की गई है कि -20वी सदी में बिहार के दलितों की स्थिति और उनके आंदोलन पर प्रकाश डाला गया है। दलित आंदोलन के पहले दौर मे अलग-

Dharmendra kumar 18.04.2024 5 R. Roushan 18.04.24

अलग जाति संगठन बनी। और किस प्रकार इन जातीय संगठनों ने अपने-अपने समुदायों में स्वतंत्र पहचान का भाव जागृत किया।

- **संजय कुमार ने अपनी पुस्तक 'बिहार की चुनावी राजनीति जाति वर्ग का समीकरण (1990 – 2015)'(2019),** में चुनावी राजनीति का विस्तृत विवरण करती है। यह पुस्तक बिहार के सामाजिक और आर्थिक इतिहास और उसकी खंडित जाति-प्रेरित और धर्म संचालित राजनीति के अंतर्निहित कारणों का भी पता लगाती है। इसके अतिरिक्त, इसमें शासन, नेतृत्व और विकास की झलक भी शामिल है। जो इस राज्य की वृद्धि और समृद्धि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण कारक है।

- **डॉ आर शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक 'भारतीय शासन एवं राजनीति'(2023),** इस पुस्तक में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य से जुड़े सभी पहलुओं को शामिल किया गया है इस पुस्तक में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारतीय संविधान का दर्शन, भारतीय संसद महासभा, भारत में दलीय व्यवस्था और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य सहित अन्य सभी आवश्यक सामग्री शामिल है तथा आधुनिक भारतीय राजनीतिक सिद्धांतों को मिलाकर विभिन्न स्रोतों से संकलित किया गया है।
- **राम मनोहर लोहिया ने अपनी पुस्तक 'द हिंदू बनाम हिंदू'(2023),** में हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और पुराना देश है। मनुष्य की इच्छा के अलावा कोई शक्ति इसमें एकता नहीं ला सकते। कट्टरपंथी हिंदुत्व अपने स्वभाव के कारण ही ऐसी इच्छा नहीं पैदा कर सकता लेकिन उधर हिंदुत्व कर सकता है। प्रस्तुत पुस्तक में जातिवाद के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, गुलामी,आजादी और उत्थान जाति प्रथा समस्या की जड़ और भाषाएं आदि महत्वपूर्ण पदों पर प्रकाश डाला गया है।

शोध आलेख -:

- **विश्वनाथ प्रसाद वर्मा ने अपने लेख, 'बिहार की राजनीतिक व्यवस्था'.(1987),** में कहा कि आजादी के साथ बिहार आगे बढ़ा. इसकी राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया। 1946 से बिहार के राजनीतिक मामलों पर श्री कृष्ण सिन्हा और अनुग्रह नारायण सिन्हा का नियंत्रण था। कृष्ण बल्लभ सहाय 1946 से 1952 तक श्री कृष्ण सिन्हा के लेफ्टिनेंट थे। 1952 के चुनाव के बाद, महेश प्रसाद सिन्हा श्री कृष्ण सिन्हा के भरोसेमंद आदमी के रूप में काम करने लगे। इसके बाद, नेतृत्व उत्तराधिकार के लिए कृष्ण बल्लभ सहाय और महेश प्रसाद सिन्हा के बीच बेरोकटोक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का सपना शुरू हुआ। इस प्रतिद्वंद्विता ने एक नियमित जाति संघर्ष के आयाम ग्रहण कर लिए जिससे न केवल अत्यधिक शत्रुतापूर्ण राजनीतिक समूह पैदा हुए बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था पर भी इसका अवांछनीय प्रभाव पड़ा। अब तक, नेताओं के राजनीतिक खेमे में उनके वफादार समर्थक होते थे। लेकिन 1952 के बाद से प्रशासकों को

6

Dharmendra Kumar 18-04-2024 R. Roushan 18.04.24

भी विभिन्न मंत्रियों और राजनीतिक आकाओं के प्रति निष्ठा के कारण प्रतिद्वंद्वी खेमों में संगठित किया जाने लगा। इससे वर्तमान तक अलग-अलग राजनीतिक बिहार के बीच एक अपवित्र संयोजन पैदा हुआ। संविधान के प्रति निष्ठा और राज्य की भलाई के प्रति प्रतिबद्धता को दूसरे नंबर पर महत्व दिया जाता है और बिहारी राजनेता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक अपने स्वार्थ की पूर्ति करना है।

- **संजय कुमार ने अपने लेख,'बिहार की चुनावी राजनीति: जाति-वर्ग का मूल्यांकन (1990-2015)'.(2019),** में बिहार राजनीतिक रूप से भारत के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है, इस क्षेत्र के कई राजनेता राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख है। बिहार में मंडल-पश्चात राजनीति 1990 के दशक से लेकर हाल ही में राजद-जद (यू)-कांग्रेस ग्रैंड अलायंस के टूटने तक बिहार की चुनावी राजनीति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक बिहार के सामाजिक और आर्थिक इतिहास और इसकी खंडित, जाति-प्रेरित और धर्म-संचालित राजनीति के अंतर्निहित कारणों का भी पता लगाती है। इसके अतिरिक्त, इसमें शासन, नेतृत्व और विकास शामिल हैं, जो महत्वपूर्ण कारक है।

- **अवधेश कुमार लाल ने अपने लेख,'कार्रवाई में दलित: बिहार दलित विकास समिति का एक मूल्यांकन'.(1997),** में दलित समाज में सबसे निचले तबके का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका शोषण एक किवदंती रही है। स्थिति के विभिन्न गुण उन्हें सामाजिक पदानुक्रम में अत्यधिक वंचित स्थान प्रदान करते हैं। वे स्थिति संबंधी अक्षमताओं के अधीन हैं। बड़े समाज के साथ उनका एकीकरण एक आकांक्षा बनी हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन की योजनाओं में दलितों की उपेक्षा की गई है। उनके मामले में सत्ता मायावी बनी हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण भी उन्हें जड़ता की स्थिति से बाहर निकालने में विफल रहा है। उन्हें निष्क्रियता की स्थिति से बाहर निकालने की तत्काल आवश्यकता है ताकि वे समाज में अपना हक जता सकें। यह एक कठिन कार्य है क्योंकि इसमें नीचे से ऊपर की क्रांति शामिल है।
- **हेमांशु कुमार, रोहिणी सोमनाथन ने अपने लेख,'जातिगत संबंध और सरकारी स्थानांतरण: बिहार के महादलित'.(2017.)** में कहा कि भारत में सकारात्मक कार्रवाई के उद्देश्य से बनाई गई अनुसूचित जाति की श्रेणी बडी, विषम और असमान है। 2007 में, बिहार राज्य ने इस समूह में सबसे अधिक वंचितों को 'महादलित' के रूप में वर्गीकृत किया, ताकि उन्हें सरकारी हस्तांतरण का बेहतर लक्ष्य मिल सके। प्रत्येक पंचायत में सबसे अधिक आबादी वाली महादलित जाति से एक 'विकास मित्र' की भर्ती की गई और उसका काम घरों को सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का संचालन करने वाले सरकारी अधिकारियों से जोड़ना था। हम बिहार के चार जिलों की 48 पंचायतों के घरेलू सर्वेक्षण डेटा का उपयोग यह पूछने के लिए करते हैं कि क्या जो परिवार विकास मित्र के समान जाति के थे, उन्हें अन्य जातियों के महादलित परिवारों की तुलना में कार्यक्रम का लाभ मिलने की काफी अधिक संभावना थी। हम इसे इंदिरा आवास योजना जैसे बड़े एकमुश्त

7

Dharmendra Kumar
18-04-2024

R. Roushan
18.04.24

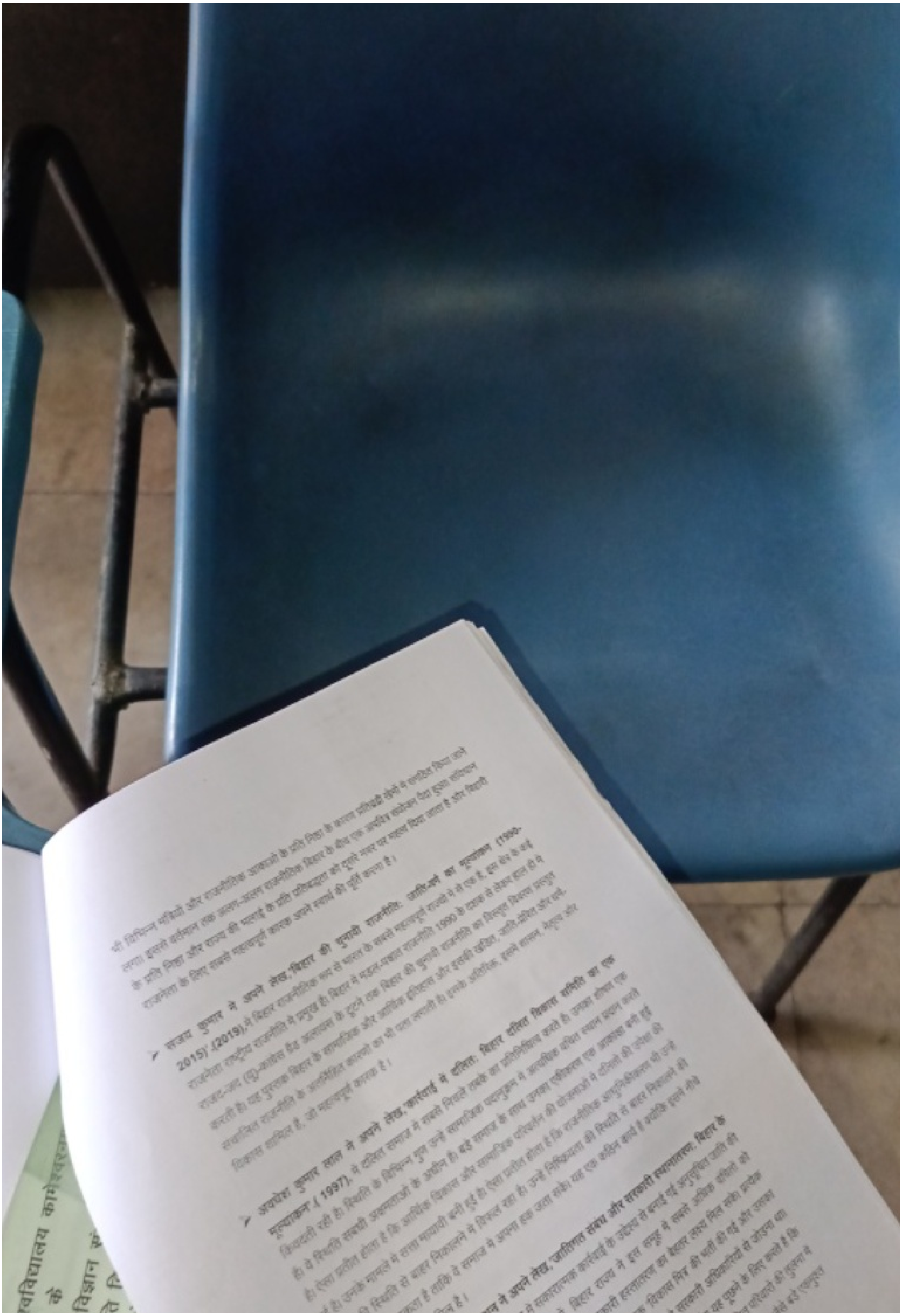

भी विभिन्न मंत्रियों और राजनीतिक आकाओं के प्रति निष्ठा के कारण प्रतिद्वंद्वी खेमों में संगठित किया जाने लगा। इससे वर्तमान तक अलग-अलग राजनीतिक बिहार के बीच एक अपवित्र संयोजन पैदा हुआ। संविधान के प्रति निष्ठा और राज्य की भलाई के प्रति प्रतिबद्धता को दूसरे नंबर पर महत्व दिया जाता है और बिहारी राजनेता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक अपने स्वार्थ की पूर्ति करना है।

- **संजय कुमार ने अपने लेख,'बिहार की चुनावी राजनीति: जाति-वर्ग का मूल्यांकन (1990-2015)'.(2019),** में बिहार राजनीतिक रूप से भारत के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है, इस क्षेत्र के कई राजनेता राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख है। बिहार में मंडल-पश्चात राजनीति 1990 के दशक से लेकर हाल ही में राजद-जद (यू)-कांग्रेस ग्रैंड अलायंस के टूटने तक बिहार की चुनावी राजनीति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक बिहार के सामाजिक और आर्थिक इतिहास और इसकी खंडित, जाति-प्रेरित और धर्म-संचालित राजनीति के अंतर्निहित कारणों का भी पता लगाती है। इसके अतिरिक, इसमें शासन, नेतृत्व और विकास शामिल हैं, जो महत्वपूर्ण कारक है।

- **अवधेश कुमार लाल ने अपने लेख,'कार्रवाई में दलित: बिहार दलित विकास समिति का एक मूल्यांकन'.(1997),** में दलित समाज में सबसे निचले तबके का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका शोषण एक किंवदंती रही है। स्थिति के विभिन्न गुण उन्हें सामाजिक पदानुक्रम में अत्यधिक वंचित स्थान प्रदान करते हैं। वे स्थिति संबंधी अक्षमताओं के अधीन हैं। बड़े समाज के साथ उनका एकीकरण एक आकांक्षा बनी हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन की योजनाओं में दलितों की उपेक्षा की गई है। उनके मामले मे सत्ता मायावी बनी हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण भी उन्हें जड़ता की स्थिति से बाहर निकालने में विफल रहा है। उन्हे निष्क्रियता की स्थिति से बाहर निकालने की तत्काल आवश्यकता है ताकि वे समाज में अपना हक जता सकें। यह एक कठिन कार्य है क्योंकि इसमें नीचे से ऊपर की क्रांति शामिल है।
- **हेमांशु कुमार, रोहिणी सोमनाथन ने अपने लेख,'जातिगत संबंध और सरकारी स्थानांतरण: बिहार के महादलित'.(2017,)** में कहा कि भारत में सकारात्मक कार्रवाई के उद्देश्य से बनाई गई अनुसूचित जाति की श्रेणी बड़ी, विषम और असमान है। 2007 में, बिहार राज्य ने इस समूह में सबसे अधिक वंचितों को 'महादलित' के रूप में वर्गीकृत किया, ताकि उन्हें सरकारी हस्तांतरण का बेहतर लक्ष्य मिल सके। प्रत्येक पंचायत मे सबसे अधिक आबादी वाली महादलित जाति से एक 'विकास मित्र' की भर्ती की गई और उसका काम घरों को सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का संचालन करने वाले सरकारी अधिकारियों से जोड़ना था। हम बिहार के चार जिलों की 48 पंचायतों के घरेलू सर्वेक्षण डेटा का उपयोग यह पूछने के लिए करते हैं कि क्या जो परिवार विकास मित्र के समान जाति के थे, उन्हें अन्य जातियों के महादलित परिवारो की तुलना मे कार्यक्रम का लाभ मिलने की काफी अधिक संभावना थी। हम इसे इंदिरा आवास योजना जैसे बड़े एकमुश्त

Dharmendra Kumar
18-04-2024

R. Roushan
18.04.24

हस्तांतरण वाले कार्यक्रमों के लिए सच मानते हैं, लेकिन सब्सिडी वाले खाद्यान्न जैसे अधिक नियमित हस्तांतरण के लिए नहीं। हमारे नतीजे बताते हैं कि भारत की अनुसूचित जातियों में जाति की पहचान प्रमुख बनी हुई है।

- **जेफरी विटसो ने अपने लेख,'बिहार'.(2013),** में 90 मिलियन से अधिक लोगों का उत्तर भारतीय राज्य, भारत का सबसे गरीब राज्य है, जो स्थानिक जातीय संघर्ष, राजनीतिक हिंसा और मजबूत होते माओवादी विद्रोह के लिए जाना जाता है। साथ ही, 1990 के दशक की शुरुआत से निचली जातियों के लोकतांत्रिक सशक्तिकरण ने राज्य के राजनीतिक भूगोल को बदल दिया है। यह अध्याय बिहार में जाति की राजनीति की जांच करेगा। जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगा, जाति सशक्तिकरण की राजनीति के परिणामस्वरूप सार्वजनिक संस्थानों का टूटना, विकास का राजनीतिक हाशिए पर जाना और आपराधिकता में नाटकीय वृद्धि हुई, लेकिन जबकि जाति-आधारित राजनीतिक लामबंदी ने शासन और राज्य की संस्थाओं को अस्थिर कर दिया- निर्देशित विकास, इसने निचली जातियों के सार्थक, यद्यपि आंशिक, सशक्तिकरण को भी उत्प्रेरित किया। विशेष रूप से, बिहार का मामला जाति प्रभुत्व, राज्य संस्थानों और चुनावी राजनीति के बीच गतिशील संबंधों को उजागर करता है जो भारत में जाति की राजनीति के केंद्र में हैं। मैं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के शासन की लंबी अवधि पर ध्यान केंद्रित करूंगा, जब लालू यादव और फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी 1990 से 2005 तक मुख्यमंत्री रहे। 2005 में मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार की शक्ति। सबसे पहले, मैं संक्षेप में उस ऐतिहासिक संदर्भ की ओर मुड़ता हूं जिसने बिहार की राजनीतिक दुनिया को आकार दिया है।
- **अन्नमणि राव ने अपने लेख,'भारत में राजनीतिक प्रक्रिया के प्रति अनुसूचित जनजातियों को सशक्त बनाने पर एक अध्ययन'.(2018),** में 'जनजाति' की अवधारणा ने औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक प्रवचनों में बहुत बहस पैदा की है, फिर भी सामाजिक मानवविज्ञानी, प्रशासकों, वकीलों, आदिवासी कार्यकर्ताओं, राजनेताओं और सरकार और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के प्रवचनों में इसके लोकप्रिय उपयोग के बावजूद, इसकी रूपरेखा में स्पष्ट परिभाषा का अभाव है। . भारत में जनजातियों की परिभाषा से ज्यादा उनकी पहचान को लेकर चिंता रही है। लोकप्रिय प्रवचन में जनजाति, अनुसूचित जनजाति, स्वदेशी लोग, वनजाति, आदिवासी और जन जैसे शब्दों का परस्पर उपयोग किया जाता है। फिर भी, प्रत्येक भारत में उपयोग और प्रतिनिधित्व के विभिन्न अर्थों और वंशावली को उद्घाटित करता है। अपने वर्तमान उपयोग में सशक्तिकरण की अवधारणा बहुत नई है, क्योंकि इसे विश्वकोश, समाजशास्त्र पाठ्यपुस्तकों के कई शब्दकोशों और शब्दावलियों में जगह नहीं मिलती है। बिटेइले (1999:589) के अनुसार, सशक्तिकरण भारतीय समाज में कुछ संदर्भों से संबंधित है। उनके अपने शब्दों में, "संक्षेप में, वह संदर्भ एक पदानुक्रमित सामाजिक व्यवस्था और एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के बीच विरोधाभास है"। वह आगे कहते हैं, "सशक्तीकरण के विचार को वस्तुतः किसी भी संदर्भ में लागू किया जा सकता है: मानवाधिकारों के बारे में, बुनियादी जरूरतों

Dharmendra Kumar R. Roushan
18.04.2024 18.4.24

के बारे में, आर्थिक सुरक्षा के बारे में, क्षमता निर्माण के बारे में, कौशल निर्माण के बारे में या सम्मानजनक सामाजिक अस्तित्व की स्थितियों के बारे में"।

- **ओलिवर मेंडेलसोहन ने अपने लेख,ए'हरिजन एलीट'?: कुछ अछूत राजनेताओं का जीवन(1986),में** 'अन्य पिछड़ों' के लिए आरक्षण पर मौजूदा हंगामा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की आम तौर पर निर्विवाद प्रणाली के विपरीत है जो स्वतंत्रता के बाद पूरे समय लागू रही है। विपरीत भेदभाव की इतनी विशाल प्रणाली इतनी अपेक्षाकृत निर्विवाद क्यों रही है? इसका सबसे बड़ा कारण लगभग 40 वर्षों के अभ्यास में अछूतों और आदिवासियों के लिए आरक्षण की अप्रभावीता है। आरक्षण उच्च या मध्यम जातियों और अछूतों या आदिवासियों के बीच सापेक्ष समृद्धि को बदलने में विफल रहा है और इसलिए इसने वह नाराजगी पैदा नहीं की है जो एक अधिक सफल योजना में होती। फिर भी यह समझना अभी भी संभव है कि इस प्रणाली ने बड़े पैमाने पर गरीबी पर उपयोगी सीमांत प्रभाव डाला है और साथ ही अनुसूचित जातियों और जनजातियो के भीतर एक समूह बनाया है जो इन समुदायों में नेतृत्व की भूमिकाओं में या तो वास्तव में या संभावित रूप से उपयोगी है। यह बाद वाला प्रश्न है – तथाकथित 'हरिजन अभिजात वर्ग' के उद्भव का – जो इस पेपर की चिंता का विषय है। चर्चा के लिए सामग्री संसद और राज्य विधानसभाओं में आरक्षित सीटों पर रहने वाले, अनुमानित अभिजात वर्ग की एक शाखा के प्रतिनिधियों के साथ साक्षात्कार के माध्यम से एकत्र की गई है।

❖ शोध का उद्देश्य (Objective of the Research):-

- बिहार के सामाजिक, आर्थिक, एवं राजनीतिक विकास में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विधायकों के योगदान का अध्ययन करना।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विधायकों का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के उत्थान में क्या योगदान रहा है इसका अध्ययन करना।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिला विधायकों का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उत्थान में योगदान का विश्लेषण उजागर करना।
- बिहार विधान मंडल में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विधायकों के योगदान का विश्लेषण करना।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विधायकों के द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए किए गए कार्यों का अध्ययन करना।
- वर्तमान समय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करना।
- अध्ययन के आधार पर तर्कसंगत एवं सही निष्कर्ष निकालना।

9

Dharmendra Kumar
18.04.2024

R. Roushan
18.04.24

❖ शोध की परिकल्पनाएं (**Research of the Hypothesis**):-

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समाज की राजनीतिक चेतना के उत्थान में उनके वर्ग के विधायकों के प्रयास से होगा।
- बिहार के विकास के लिए अनूसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का योगदान अपरिहार्य है।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विधायकों के बिहार विधानमंडल में नीति निर्माण से उनके सामाजिक,आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में सुधार होगा।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त होने से उनके सामाजिक,आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष विधायको एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिला विधायकों की राजनीतिक प्रभावशीलता सामान रही।

❖ **प्रस्तुत शोध कार्य का अनुशासन एवं अन्य अनुशासन के लिए योगदान (Contribution of the research work to the discipline and other discipline):-**

इस शोध के माध्यम से राजनीति विज्ञान के साथ-साथ समाजशास्त्र, आर्थिक सशक्तिकरण तथा ऐतिहासिक पहलू का अध्ययन करेंगे ताकि इतिहास और अर्थशास्त्र के विषय पर इस शोध का लाभ प्राप्त हो सकेगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विधायकों को सत्ता में आने से बिहार के विकास में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित योगदान की नवीन जानकारी प्राप्त होगी।

❖ **शोध प्रविधि (Methodological Approach):-**

प्रस्तुत शोध कार्य को पूरा करने के लिए ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक, गुणात्मक और मात्रात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाएगा साथ ही प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोत को लिया जाएगा।

- प्राथमिक स्रोत (**Primary Source**)- प्राथमिक स्रोत पूर्ण रूपेण सरकारी दस्तावेजों पर आधारित होगा संविधान विशेषज्ञों के भाषणों, विधानसभा सचिवालय, विधानमंडल के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विधायकों के साक्षात्कारों, बिहार विधानसभा के कार्रवाई एवं राजनितिक दलों की संविधान पुस्तकों का अध्ययन किया जाएगा तथा प्रश्नावली , अनुसूची आदि का उपयोग किया जाएगा।

Dharmendra Kumar 18-04-2024 10 R. Roushan 18.04.24

➤ द्वितीयक स्रोत (**Secondary Source**)-:द्वितीयक स्रोत मूलतः दैनिक समाचार पत्र, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, विधानसभा पुस्तकालय पटना , विकास भवन पटना तथा राज्य निर्वाचन निदेशालय एवं जनसंपर्क विभाग से सूचनाएं एकत्रित की जाएगी।

❖ **कार्य प्रारूप: अस्थायी कार्य योजना (Work design : Tentative plan of the work)-:**

अध्याय 1 : परिचय।

अध्याय 2 : साहित्य का पुनर्विलोकन।

अध्याय 3 : बिहार के विकास में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियां।

अध्याय 4 : बिहार विधानमंडल के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विधायकों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति एवं क्रियाकलापो का अध्ययन।

अध्याय 5: बिहार के विकास में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विधायकों तथा संबंधित वर्गों के मुख्यमंत्रीयो का अध्ययन।

अध्याय 6 : निष्कर्ष।

❖ संदर्भ सूची(**References**))-:

- झा,ए.एम. एवं ठाकुर, मिन्नी.(2012) बिहार सुशासन की ओर. दिल्ली: मीनाक्षी प्रकाशन.
- मिश्रा,डॉ.जगन्नाथ.(2012). बिहार विकास और संघर्ष.पटना: नोवेल्टी एंड कंपनी.
- झा,पंकज कुमार.(2010). सुशान के आइने में नया बिहार. नई दिल्ली: प्रभात प्रकाशन.
- सिन्हा,अशोक कुमार.(2021). बिहार के 25 महानायक.पटना: प्रभात प्रकाशन.
- कोठरी, रजनी (2010). कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स. दिल्ली: वाणी प्रकाशन.
- कोठारी,रजनी.(2005).भारत में राजनीति (कल और आज). दिल्ली: वाणी प्रकाशन.
- दत्त,महेश्वर.(2005). गांधी अंबेडकर और दलित .नई दिल्ली: राधा पब्लिकेशन .
- राजकिशोर,(2008). दलित राजनीति की समस्याएं. दिल्ली: वाणी प्रकाशन.

Dharmendra kumar 18-04-2024 R. Raushan 18.04.24

- चौधरी,प्रसन्न कुमार और श्रीकांत.(2015).स्वर्ग पर धावा - बिहार में दलित आंदोलन (1912-2000).दिल्ली: वाणी प्रकाशन.
- Chandrachud, Abhinav.(2023).These seats are reserved caste, quotes and the constitution of India.Haryana : Penguin Random House India.
- शर्मा, डी. आर.(2008). भारतीय शासन और राजनीति. नई दिल्ली: भारतीय आकाशवाणी प्रकाशन.
- लोहिया,राम मनोहर.(2023).हिंदू बनाम हिंदू. प्रयागराज: लोकभारती प्रकाशन.
- संजय कुमार.(2019). बिहार की चुनावी राजनीति जाति-वर्ग का समीकरण(1990-2015). दिल्ली: फारवर्ड प्रेस.
- प्रसाद, प्रधान हरिशंकर एवं दत्त, मीरा.(2017). आर्थिक विकास: बिहार की त्रासदी. पटना: बिहार हिन्दी ग्रन्थ आकदमी.

शोध आलेख:-

- वर्मा, वीपी, और वर्मा, वीपी (1987)। बिहार की राजनीतिक व्यवस्था. द इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस , 48 (4), 506-511।
- कुमार, एस. (2019)। बिहार की चुनावी राजनीति: जाति-वर्ग का समन्वय (1990-2015) । सेज प्रकाशन प्रा. सीमित ।
- लाल, एके (1997)। कार्रवाई में दलित: बिहार दलित विकास समिति का एक मूल्यांकन । संकल्पना प्रकाशन कंपनी ।
- कुमार, एच., और सोमनाथन, आर. (2017)। जाति संबंध और सरकारी स्थानांतरण: बिहार के महादलित (संख्या 270)।
- विटसो, जे. (2013)। बिहार. रूटलेज हैंडबुक ऑफ़ इंडियन पॉलिटिक्स में (पृ. 298-307)। रूटलेज ।
- राव, केए (2018)। भारत में राजनीतिक प्रक्रिया के प्रति अनुसूचित जनजातियों को सशक्त बनाने पर एक अध्ययन। आईओएसआर जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस (आईओएसआर-जेएचएसएस) खंड , 23 , 58-63 ।

12

Dharmendra Kumar
18.04.2024

R. Roushan
18.04.24

- मेंडेलसोहन, ओ. (1986)। एहरिजन एलीट'?: कुछ अछूत राजनेताओं का जीवन। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली , 501-509 ।

R. Roushan 18.04.24

शोध पर्यवेक्षक हस्ताक्षर

Dr. Rajeev Roushan
Assistant Professor & Head
Dept. of Political Science
R.N.A.R. College, Samastipur

Dharmendra Kumar 18-04-2024

शोधार्थी हस्ताक्षर

20/4/24

MB 20042024

20/4/24

20.04.24

20.4.24